[*Setting up of a full-fledged embassy in the Peoples Republic of Mongolia.* (71)].

"That the Demand under the Head External Affairs be reduced by Rs. 100."

[*Need for initiating and sustaining friendly policies in relation to all our neighbour States.* (72)].

"That the Demand under the Head External Affairs be reduced by Rs. 100."

[*Need for fresh imaginative and courageous initiatives for securing friendly relations with Pakistan.* (73)].

"That the Demand under the Head External Affairs be reduced by Rs. 100."

[*Problems of recruitment of our diplomatic personnel and ensuring proper orientation in their work.* (74)].

"That the Demand under the Head External Affairs be reduced by Rs. 100."

[*Ways and means of terminating the present undesirable relations with the People's Republic of China.* (75)].

"That the Demand under the Head External Affairs be reduced by Rs. 100."

[*Need for improving our work in the United Nations and its agencies.* (76)].

"That the Demand under the Head External Affairs be reduced by Rs. 100."

[*Generally unsatisfactory working of our missions abroad.* (77)].

SHRI RANGA (Srikakulam): I beg to move:

"That the Demand under the Head External Affairs be reduced to Re. 1."

[*Failure of the Government to play an effective role in developing regional security arrangements for the defence of South and South-East Asia from Chinese Communist expansionism in collaboration with the countries of South-East Asia, Japan and Australasia, the need for which has become more urgent in view of recent developments.* (78)].

MR. DEPUTY-SPEAKER: The Cut Motions are also now before the House.

18.29 hrs.

EXPANSION* OF TRADE WITH SOCIALIST COUNTRIES

श्री कामेश्वर सिंह (खगरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, एक बात सबसे मार्के की यह है कि सोशलिस्ट कंट्रीज के साथ ट्रेड में तो हम लोगों ने ट्रैडिशनल कंट्रीज पर डिपेन्डेन्स कम कर दिया है, परन्तु मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि पिछले अक्तूबर में प्रधान मन्त्री ईस्ट योरोपियन कण्ट्रीज गई थीं और वहां पर व्यापारिक समझौतों के बारे में बहुत सी बातें हुई थीं और समझौते भी हुए थे। मैंने कम्यूनिकके में पढ़ा था। परन्तु अभी तक इस मामले में समझौते के बाद क्या कदम उठाया गया है जिससे हमारे व्यापारिक रिश्ते और सुदृढ़ हो सकें, तथा हमारे देश की एक्सपोर्ट ईस्ट योरोपियन कण्ट्रीज के साथ बढ़े, इस मामले में कोई बातचीत हुई या नहीं, इस का कोई पता नहीं चला। मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि अक्सर हमारे मन्त्रीगण विदेश जाते हैं और वहां से उनके वापस लौटने के बाद सारा मामला ठंडा पड़ जाता है। परन्तु चूंकि इस मामले में प्रधान मन्त्री का हाथ है, इसलिये मैं जानना चाहूंगा कि अभी तक क्या हुआ।

अभी अभी हाल में बहुत चर्चा चल रही है कि रूस हिन्दुस्तान का बहुत सा रेल का सामान खरीदने वाला है। परन्तु जहां तक

---

*Half-An-Hour Discussion.

[श्री कामेश्वर सिंह]

मैं जानता हूं, रूस में जो रेलवे का सामान इस्तैमाल होता है और हमारे देश में जो सामान बन रहा है, उन दोनों के स्पेसिफिकेशन में काफी अन्तर है। क्या मन्त्री महोदय मुझे यह बतलायेंगे कि जो सामान यहां से रूस जायेगा वह हमारे स्पेसिफिकेशन का एक्सपोर्ट होगा या रशियन स्पेसिफिकेशन के मुताबिक बन कर एक्सपोर्ट होगा? कभी कभी ऐसा होता है कि एक देश हम से सामान खरीद कर ले जाता है और वह सामान वहां पहुंच भी नहीं पाता है और दूसरे मुल्कों को वह उसे बेच देता है। कुछ साल पहले चीन ने क्यूबा से चीनी खरीदी थी, लेकिन वह चीनी चाइना पहुंचने के पहले ही बेच दी गई। इसका नतीजा यह हुआ कि विश्व के अन्य बाजारों में चीनी का भाव बहुत घट गया तथा इसका नतीजा भारत को भी भोगना पड़ा।

सोशलिस्ट कण्ट्रीज से हमारा ट्रेड बहुत बढ़ गया है, इस को हमने मान लिया, परन्तु अभी तक हमारी सरकार ने नान-ट्रैडिशनल आइटेम्स को एक्सपोर्ट करने की दिशा में जो कदम उठाया है वह नहीं के बराबर है। अभी तक हम लोग कच्चा माल ही एक्सपोर्ट करते हैं। जहां तक हमारे फिनिश्ड गुड्स का सवाल है, कपड़ा यहां से खरीद कर ले जाया जाता है। ईस्ट योरोपियन कण्ट्रीज का एक ही उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। यह चिट्ठी श्री रत्नम ने लिखी है जो कि टैक्सटाइल आफिसर हैं।

"My dear Ambassador,

When I met you in Rotterdom on 27th April, I gave a brief report to you about the switch trade in our cotton textiles practised by some of the East European countries. During my recent survey of the Netherlands market, I was informed by two leading importers that Indian grey cloth brought by Eastern Europe finds its way to Netherlands at cheaper price. The *modus operandi* appears to be as follows: Some of the leading importers of Indian cotton greys also have connections in East Europe and import greys from these countries. Our cloth brought by East Europe is shipped from Bombay to Trieste. In Trieste, the bales are diverted to Rotterdam to the account of the importer. In Netherlands it has been reported that countries like Bulgaria, Hungary and Rumania etc. have some sort of an organisation in Trieste to carry out the switch trade smoothly."

18.33 hrs.

[SHRI BAL RAJ MADHOK *in the Chair*]

मैंने आप से पहले भी यह बतलाया है कि यह उस मुल्क को पहुंचने के पहले ही बेच दिये जाते हैं और श्री रत्नम की जो चिट्ठी है वह इस को साफ जाहिर करती है। हमारे मन्त्री जी कहेंगे कि यह चिट्ठी गलत है। हो सकता है कि समूची फाइल ही इस चिट्ठी को गलत साबित करने के लिये उड़ा दी जाये या हो सकता है कि इस अफसर को सैक करें। परन्तु सच कभी छिप नहीं सकता है। आगे वह कहते हैं:

"I was informed confidentially that our grey construction 30/30" 68X68 50" is the principal sort that is diverted to Netherlands at 15 per cent lower prices."

"We know that considerable quantities of this construction is being brought from us by east European countries also.

One importer, who wanted his name to be kept out, even frankly confessed that he would not like to buy grey cloth directly from us when he can get our greys from eastern Europe at 15 per cent lower prices.

The reason why Netherlands has been chosen for this switch trade is due to lack of import restrictions on the one hand and very few customs formalities on the other hand."

हमारे मन्त्री महोदय कहेंगे कि यह बात बिल्कुल गलत है । अगर वह ऐसा कहते हैं तो मैं समझूंगा कि इसका अर्थ यह है कि हमारे जो ट्रेड अटैचीज़ विदेशों में हैं उनकी जो कर्मशियल इंटैलीजेंस है वह फेल हो गई है । उनको पता ही नहीं चलता है कि उनके पैरों के नीचे क्या हो रहा है । वे गलत सूचनायें मन्त्रियों को देते हैं । क्योंकि हम लोग इस बात को उनको बता रहे हैं इसलिए हो सकता है कि मन्त्री महोदय कहें कि यह सरासर गलत बात है । जो सही बात है उसको तो मन्त्री लोग कभी मानने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं ।

मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि सोश-लिस्ट कण्ट्रीज़ के साथ हमारी ट्रेड बढ़नी चाहिये । परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि हम लोग उनकी हर जायज और नाजायज बात को मानें और वे जो कुछ भी कहें उसको आंख मूंद कर मान लें ।

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : कौन सी कण्ट्रीज़ हैं नाम लो ।

श्री कामेश्वर सिंह : सभी हैं । अगर आप मन्त्री हों तो आप को पता चले । यह रतनम साहब की चिट्ठी है जो कि टैक्सटाइल के एक्सपर्ट माने जाते हैं ।

मशीनरी जो आती है वह भी काफी दामों पर आती है । हमारे यहां से चाय, काफी आदि अन्य देशों को भेजी जाती हैं । ये हमारी ट्रेडीशनल एक्सपोर्ट की आइटम्ज़ हैं ।

जहां तक चमड़े का सम्बन्ध है उसकी भी एक बहुत मजेदार बात मैं आपको बतलाना चाहता हूं । कुछ साल पहले रूस ने हम से चमड़ा खरीदा और हमारी मार्किट प्राइस से पच्चीस परसेंट ज्यादा प्राइस पर खरीदा । इसका नतीजा यह हुआ कि मद्रास में जो लोकल टैनरीज़ थी उनमें करीब पन्द्रह बीस हजार आदमी अनएम्प्लायड हो गए । वे बन्द हो गई क्योंकि उनको चमड़ा नहीं मिला । दूसरे साल इसने खरीदना बिल्कुल कम कर दिया । इसका नतीजा यह हुआ कि जो इसके ट्रेडीशनल इम्पोर्टर्ज़ थे उन्होंने भी हम से नहीं खरीदा । रूस ने भी नहीं खरीदा और उन्होंने भी नहीं खरीदा । इस वास्ते मैं जोर दे कर कहना चाहूंगा कि ट्रेड एग्रीमेंट्स इस तरह के होने चाहिये कि जो देश हम से कच्चा माल खरीदें उनके साथ हम लांग टर्म एग्रीमेंट करें । ऐसा नहीं होना चाहिये कि जैसे रूस ने किया कि एक साल तो उसने खरीद लिया लेकिन दूसरे साल खरीदा ही नहीं । यही हाल काजू का भी हुआ । कितने ही इस तरह के उदाहरण हैं ।

अब मैं प्रश्न करूंगा । प्रधान मन्त्री जी अक्तूबर महीने में पूर्व यूरोप के देशों में गई थीं । मैं जानना चाहता हूं कि उनके लौटने के बाद आपने क्या फालो अप एक्शन लिया और उसके क्या परिणाम निकले ?

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि स्विच ट्रेड की जो धांधली चल रही है इसके बारे में मन्त्री महोदय ने क्या कदम उठाया है इसको भी बतलाने की वह कृपा करें ।

श्री शिंकरे (पंजिम) : समाजवादी देशों से हमारा जो व्यापार होता है उसकी मैं उपमा कमल पर पानी की बूंद से दूंगा । हमारा जो व्यापार समाजवादी देशों से होता है उसके पीछे समाजवादी देशों के पोलिटिकल उद्देश्य रहते हैं । जब उनके वे उद्देश्य खत्म हो जाते हैं तो वह व्यापार भी खत्म हो जाता है । मेरा ख्याल है कि समाजवादी देश भारत में पैदा होने वाली वस्तुओं को इसलिए खरीदते हैं कि ब्रिटेन, अमरीका आदि साम्राज्यवादी

[श्री शिकरे]

देशों को यहां मार्किट न मिले । वे हमारा कल्याण नहीं चाहते हैं । वे चाहते हैं कि ब्रिटिश और अमरीकी व्यापारियों को यहां मार्किट न मिले । इस वास्ते हमें सोचना पड़ेगा कि क्या दूसरी कोई मार्किट्स हैं या नहीं है जहां हम अपने माल को भेज सकें । मिडल ईस्ट की मार्किट हम को मिली है और समाजवादी देशों की मार्कीट भी मिली है । लेकिन मैं समझता हूं कि भारत को कोई ऐसी नई मार्किट्स देखनी चाहियें जहां उसका माल हमेशा भेजा जा सके और वहां वह बिक सके । आपके सामने साउथ अमरीका के देश हैं, जिन को लैटिन अमरीका के देश कहते हैं, वे हैं । मैं जानना चाहता हूं कि इन देशों में हिन्दुस्तान में पैदा होने वाले माल के लिए मार्किट आपने ढूंढी है क्या, इसका पता आपने लगाया है क्या और इस ओर कदम बढ़ाये हैं क्या ? अंकटाड का अधिवेशन अभी हाल में यहां हुआ था । वहां ब्राजील से, चिली से तथा अनेक लैटिन अमरीकी देशों से प्रतिनिधि आए थे । मैं चाहूंगा कि इन देशों से भारत का व्यापार ज्यादा हो । इसलिए मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या इसके बारे में कोई कदम उठाया जाएगा क्या ?

SHRI SRADHAKAR SUPAKAR (Sambalpur): The original question related to only one year. I should like to know how far have we progressed in our trade relations with the socialist countries, specially East European countries and how far the allegations made in the alleged letter written by one Mr. Ratnam read out by the mover are correct? May I know whether on account of such allegations, we are discouraged from increasing our trade relationship with these countries. In view of the fact that on account of the complications arising out of the UK trying to join the ECM and the consequent possible shrinkage of our trade relations with UK, which is one of our best trading countries both in regard to imports and exports, what steps are we going to take to see that our trade relationship with the socialist countries develops? What is the progress in this regard during the last few years?

SHRI S. S. KOTHARI (Mandsaur): Some tilt in the delicate balance of India's policy of non-alignment had become inevitable, consequent upon the increasing dependence upon Soviet Union's economic and defence aid. Conspicuous now is the Russian offer to absorb about Rs. 100 crores worth of wagons and engineering goods to extract the Indian economy out of the economic morass and recession. Ostrich-like, the Government is closing its eyes to the growing Russian influence on our economy. The consequence is that the Government is unable to adopt a strong policy towards the communists on whom a mantle of respectability has been conferred by this Government on account of dependence on Russia. The sale to Russia of our engineering goods and wagons is likely to be made at prices lower than the normal prices. It would be in the nature of a forced sale. I would urge the Government to be cautious while signing this trade agreement, so that this country does not have to suffer by selling at prices lower than normal prices. May I observe that exports to East European countries have generally been at the expense of exports to free currency areas.

Another point—and that is an important one—is that imports are being made from these socialist countries at prices which are higher than world prices; that is, both ways we suffer—the exports are at a lower rate and the imports are at a higher rate than the rates prevailing in normal free trade.

Another point is that most of the goods that are exported to the socialist countries often find their way directly or indirectly to the West European

markets and that is to the detriment of our trade with West European countries.

In view of the points that I have made, I would urge upon the Minister to consider and let us know to what extent and in what manner he is going to guard against these contingencies, particularly with regard to the terms of trade.

श्री रणधीर सिंह : चेयरमैन महोदय, हमारे देश की तिजारत सदियों से मिडिल ईस्ट के साथ खास तौर पर ईराक, अरेबियन कण्ट्रीज, मिश्र, मेडिटरेनियन कण्ट्रीज़, इटली वगैरह और फिर यूरोप के साथ होती हुई चली आई है। जो अंग्रेज़ के वक्त में पालिसी थी और जो अब हमारी पालिसी चलती है उस में गवर्नमेंट आफ़ इंडिया ने कोई नयी पालिसी ज्यादा से ज्यादा ट्रेड रिलेशंस बढ़ाने के लिए बनायी है क्या ? अपनी आमदरफ्त बढ़ाने, अपने बरामद और दरामद बढ़ाने के लिए क्या खास तौर पर इकदामात उन्होंने उठाये हैं ?

(2) खास तौर पर उन कण्ट्रीज जैसे इसरायल है, डेन्मार्क है, और जिन को हम सोशलिस्ट कण्ट्रीज़ कहते हैं, जब कि हम भी अपने को सोशलिस्ट कण्ट्री होने का दम भरते हैं, तो उन के साथ क्या खास इम्तयाज़ हम ने ट्रेड रिलेशंस में रखी है ताकि एक भाई चारे के नाते, हम भी सोशलिस्ट हैं और वह भी सोशलिस्ट हैं, इस नाते हमारा आपस में ट्रेड बढ़े, इस के लिए कोई पालिसी, नेशनलाइजेशन की पालिसी हम सोच रहे हैं जिस में उन कण्ट्रीज़ के साथ हम ज्यादा से ज्यादा बरतें, हमारा माल ज्यादा से ज्यादा उन कण्ट्रीज़ में लिया जाय और उन लोगों का माल ज्यादा से ज्यादा हमारी जरूरियात को पूरा करे ? मैं हुकमत से जानना चाहता हूं, वह इसके ऊपर रोशनी डाले ।

श्री तुलशीदास जाधव (बारामती) : चेयरमैन साहब, यह बाहर के देशों से जो अपना व्यापार होता है, उसमें अमेरिका, इंग्लैंड में जो माल जाता है, आंकड़ों को देखने से पता चलता है उस से समाजवादी देश को माल भेजने में दिक्कत पैदा होती है क्या? जैसे अमेरिका को या इंग्लैण्ड को भेजा तो किसी समाजवादी देश से मांग आई तो वहां उस की वजह से माल नहीं भेज सकते, ऐसा हुआ है क्या ?

दूसरा सवाल यह है कि समाजवादी देशों में माल भेजने से समाजवादी विचार आचार को पुष्टि मिलेगी और दूसरी प्रवृत्ति कम होती जायेगी, इस दृष्टि से यह व्यापार समाजवादी देशों से करने की गरज मालूम होती है या नहीं ?

तीसरी बात-यहां से बाहर जो व्यापार होता है जहां तक मैंने सुना जब मैं बाहर गया था उस वक्त कि माल बताने में एक चीज होती है और भेजते समय दूसरी खराब चीज भेजते हैं जिस से सब देशों में भारत के लिए एक ओपिनियन अच्छी नहीं है, तो इस का कोई असर इस व्यापार के अन्दर इस देश में हुआ है क्या ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI): Sir, hon. Member know that India has bilateral agreements with many countries and of these the most important agreements are with the eight East European countries. We have got to look to the development of trade between India and the East European countries and we should derive a sense of satisfaction that our trade with these countries has developed on a bilateral basis. The essence of this trade, as we see, is that whereas in the decade 1956-57 to 1965-66 our total exports to all destinations increased by 34 per cent, that is, from Rs. 604 crores to Rs. 810 crores. Our exports to these eight East European countries multiplied $7\frac{1}{2}$ times, that is, from Rs. 21 crores to Rs. 157 crores. In other

[Shri Mohd. Shafi Qureshi]

words, out of a total increase in exports of about Rs. 206 crores, in that particular time, the East European countries accounted for no less than Rs. 136 crores. Our imports from this group of countries have also increased considerably.

The expansion of exports and imports under this system has helped the country to have a more balanced international trade. Not only has the composition of this trade been in accordance with our national priorities, but, more important thing is that the unorthodox method of payment, featuring "counter-patronage", has given us considerable advantage in our development programme.

Because of the scheme of bilateralism, our essential imports are being continuously paid for by the exports of goods of a matching value rather than in terms of free foreign exchange. One can very well imagine that if we had to import heavy machinery and equipment from these western countries, it would have been at the cost of a great erosion of our foreign exchange resources which we could little afford at this time.

SHRI PILOO MODY (Godhra): What do we export?

SHRI MOHD. SHAFI QURESHI: I will give the figures.

Thus as against the convertable currency trade with the rest of the world, I would just enumerate the advantages in this bilateral balance trade.

We import only those items which are most necessary for our economy at comparable prices for matching quality. We buy nothing from the rupee countries which we do not import from other sources. My hon. friend raised doubts that we are purchasing certain things which are unnecessary for our country and that we are paying a higher price for them. This is not correct. In bulk purchases, the House will see that because of the agreement that we have entered into with different East European countries, they are supplying us goods at very competitive rates without any depletion of our foreign exchange resources.

SHRI KAMESHWAR SINGH: Inferior quality.

SHRI MOHD. SHAFI QURESHI: Not inferior quality. After all, we are the buyers and, as a conscientious buyer we are buying the goods of the best quality. I can assure the House that East European countries are sending the best quality they can afford.

SHRI PILOO MODY: What do we export in its place?

SHRI MOHD. SHAFI QURESHI: I will give the figures.

The second advantage that we have is that we borrow technology and technical know-how from these countries on a long-term basis and the capital goods on a long term basis and we have to pay these loans, not in terms of currency of that country, but we have to pay through exports of goods leaving no residue, or burden to heavy foreign debts.

My hon. friend knows that we are now not only exporting traditional goods to these East European countries but we have made a shift and you will see what goods we could not sell in western countries, we have found a very good market in East European countries and these countries have proved to be a stepping stone for us to make dents in other developed countries of the world. We are grateful to these countries for the help they have rendered to us.

The third advantage is that it promotes exportability of new items of our manufacture which otherwise face stiff competition in the industrialised world in the initial stages and, as I said earlier, would not have found markets. For instance, our sales of

footwear, machine tools, refrigerators, fruit juices, thermos flasks, surgical gloves, knitwear and other engineering goods and chemicals to the East European countries through these trade plans have eventually enabled us to sell them in the Western markets also. Thus the rupee trade helps as a stepping stone to train and build up our exports and to achieve expertise and confidence to sell these new and difficult-to-sell items in the fiercely competitive and sophisticated world markets.

Then, the unit price that we fetch for our exports is levelled upwards by the bulk buying by these centrally planned and controlled economies with full freedom to us to pay international prices for goods which we buy from these countries for our basic requirements. So, we are not paying a penny higher than the international prices which we would have normally paid had we purchased the same from the Western countries.

Then, we lift the seasonal surplus of our farms and plantation products which would otherwise have depressed our production.

My hon. friend, Mr. Kameshwar Singh made a point about the switch trade. His grievance is that the Indian goods go to the Port of Trieste and from there, the goods which are meant for the destinations in East European countries are switched over to some West European countries and there, they are sold at 15 per cent lesser price. If, according to him, our goods are sold at 15 per cent less as compared to the price which we get rom the East European countries, it is not a switch trade because the East European countries are giving us more money. If some country sells at 15 per cent less, and is giving us more, we must be grateful to that country which is giving us more. How does he say.... (*Interruptions*).

श्री कामेश्वर सिंह : सभापति महोदय, इस से हमारे यहां फौरन-एक्सचेंज नहीं आती है। जिस चीज को हम डाइरेक्ट पश्चिम यूरोपियन कण्ट्रीज को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वे लोग इम्पोर्ट भी करना चाहते हैं, लेकिन ये ईस्ट यूरोपियन कण्ट्रीज हमारे उस माल को मंगा कर 100 रु के माल को उन को 85 रुपये में बेचते हैं। मंत्री महोदय ने हम को गलत समझा है।

SHRI MOHD. SHAFI QURESHI: I think, I have not been....

MR. CHAIRMAN: I will tell him. The hon. Member says that the foreign exchange that we would have not from western countries, we do not get by this kind of trade.

SHRI MOHD. SHAFI QURESHI: I have not been able to make myself clear in English. So, I will speak in Hindi.

चेयरमैन साहब, मेरी इस्तदुआ यह है कि जहां तक स्विच ट्रेड का ताल्लुक है—यह कहा गया है कि हमारी चीजें जो ईस्ट यूरोपियन कण्ट्रीज को जाती हैं, वे वहां से दूसरे मुल्कों को चली जाती हैं और इस तरह से वे मुल्क फौरन-एक्सचेन्ज कमाते हैं और हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचता है। इस किस्म की शिकायतें जब हमारे पास आई और जब हमने वाक्यात को कसौटी पर रखा, तो हमने पाया कि ये सब बातें गलत हैं। मैं पूरे वसूख के साथ और ईमानदारी के साथ इस हाउस को कहना चाहता हूं कि हम ने इस बात की मुकम्मिल तहकीकात की है। लेकिन कुछ ऐसी बातें भी हुई हैं कि जहां पर हमारे एक्सपोर्टर्ज ने खुद गलत डेस्टीनेशन के लिए माल भेजा, उस के लिए हमें शरमिन्दा होना चाहिए। इसलिए यह कहना गलत है कि वे मुल्क इस किस्म की बात करते हैं। यह गलत है कि वहां पर स्विच ट्रेड होता है।

[Shri Mohd. Shafi Qureshi]

मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि अनटाड-2 में एक यूनैनिमस रेजोल्यूशन पास हुआ है :—

It was unanimously adopted in UNCTAD-II that there would be no reexport of goods imported from the developing countries by the socialist countries.

जो माल एक डेवेलपिंग कण्ट्री से दूसरी डवेलपिंग कण्ट्री को जायगा, वह उसी मुल्क में जायगा और तब तक उस मुल्क से बाहर नहीं जायगा, जब तक भेजने वाला मुल्क उसकी इजाजत न दे। इस लिए हमें इस पर भरोसा होना चाहिए। जब एक इन्टरनेशनल फोरम के तमाम मुल्क, जो सोवरन हैं, इस किस्म का वायदा करते हैं कि स्विच ट्रेड नहीं होगा, तो हमें एतबार है कि वे अपने वायदे पर कायम रहेंगे।

श्री रबि राय (पुरी) : क्या पहले होता था, जो आगे चल कर नहीं होगा— यह आप कैसे कह सकते हैं ?.

श्री शशि भूषण बाजपेयी (खारगोन) : चेयरमैन साहब, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं : जो रेलवे वैगन्ज हम देने जा रहे हैं और जिसे दुनिया के कई मुल्क लेना चाहते हैं, क्या वह हमारे पास सरप्लस थी ? दूसरे जो माल वेस्ट जर्मनी को भेजते रहे, वह कभी सोशलिस्ट कन्ट्रीज को भेजते थे या नहीं ?

श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी : शिकायत थी, लेकिन कोई स्पेस्फिक मामला आज तक गवर्नमेंट की नोटिस में नहीं लाया गया और न ही किसी ऐसे मामले की तहकीकात हुई है।

श्री रबि राय : रत्लम वाले मामले की जांच करवाई है, क्या ?

श्री ओम प्रकाश त्यागी (मुरादाबाद) : अभी आपने कहा कि हमारा माल 25 परसेंट कम पर लेती हैं और 15 परसट कम पर देती हैं. . .

श्री महम्मद शफ़ी कुरेशी : जी नहीं, यह नहीं कहा है। यह कहा गया है कि जो माल यहां से जाता है, वह दूसरी जगह 15 परसेन्ट कम पर बिकता है। इस तरह से भी हम को तो अच्छी कीमत मिल गई, अगर हम उस मुल्क को भेजते तो हम को भी 15 परसेन्ट कम मिलता।

जहां तक शशि भूषण जी के सवाल का ताल्लुक है, यह हमारे लिए एक बड़ी कामयाबी की बात है कि एशिया और दूसरे मुल्कों से हम ने इस तरह के एग्रीमेन्ट किये हैं। ग्लोबल टेण्डर के खिलाफ हम ने अपना टेण्डर दिया था और हमारा टेण्डर उस में कामयाब हुआ, हमारे रेट्स तमाम दुनिया और यू० एस० ए० जैसे मुल्कों के मुकाबले में कम्पीटीटिव रहे। उनके साथ जो एग्रीमेन्ट हुआ है, उस पर उन्होंने गारण्टी दी है कि जितनी भी तादाद हम 1975 तक बनायेंगे, वे सब का सब लेने को तैयार हैं। जहां तक स्पेस्फिकेशन का सवाल है, माननीय सदस्य को सोचना चाहिए कि जो चीज हिन्दुस्तान बनाये, वह नहीं बिकेगी. हम को अपने इम्पोर्टर की जरूरत को कैटर करना होगा, उनके स्पेस्फिकेशन के मुताबिक उन को वैगन सप्लाई करनी है।

Because we cannot sell everything Indian as sacrosanct, and we have to satisfy the importer at the other end.

श्री तुलशी दास जाधव : क्या इस के चलते हम को कोई लौस होगा ?

श्री महम्मद शफ़ी कुरेशी : जो वैगन्स हम दे रहे हैं, उस में कतई नुकसान नहीं होगा, उस को फायदे से बेच रहे हैं। यह एक बहुत अच्छी बात है कि हम अपनी ट्रेडीशनल चीजों से नई चीजों की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। पहले हम दालचीनी, काली मिर्च, गरम मसाला,

लौंग, इलायची, काफ़ी, चाय वगैरह भेजा करते थे, लेकिन यह खुशी की बात है कि अब हम रेलवे वैगन्स भेज सकते हैं, इन्जीनियरिंग का सामान भेज सकते हैं और दूसरी चीजें भेज सकते हैं ।

श्री इसहाक सम्भली (अमरोहा) : अभी आपने फरमाया कि हमें कुछ शरमिन्दगी उठानी पड़ी, बाज लोगों ने नमूने कुछ भेजे और माल कुछ भेजा । मैं यह मालूम करना चाहता हूं कि वे नमूने कुछ भेजने वाले और माल कुछ भेजने वाले क्या स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन के लोग थे या प्राइवेट सैक्टर में काम करने वाले बिजनेसमैन थे ?

श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी : जिस वक्त ईस्ट यूरोपियन कन्ट्रीज में जूता भेजना शुरू किया तो आगरा के कुछ लोगों ने स्पेसिफिकेशन के खिलाफ़ माल भेजा । इसी वजह से यह फैसला किया गया कि इस किस्म की तमाम ट्रेड आइन्दा एस० टी० सी० की मराफत कैनलाइज हो । मैं यह बात भी सदन को बताना चाहता हूं कि जब से एस० टी० सी० ने जूतों के निर्यात का काम अपने हाथ में लिया है, हमारी क्वालिटी बढ़ गई है, जूती की तादाद बढ़ी है, बल्कि हम ने अमरीका जैसे मुल्क में अपने लिए मार्किट बना लिया है । इस में एस० टी० सी० का कोई दोष नहीं था, बल्कि प्राइवेट एक्सपोर्टर्ज की इस खराबी को रोकने के लिए हम ने यह फैसला किया कि जो भी कारोबार होगा एस०टी० सी० के ज़रिये होगा ।

हमारे सिंकरे साहब ने यह कहा कि लैटिन-अमरीकी कण्ट्रीज के साथ हमारे तिजारती सम्बन्ध बढ़ने चाहिएं । इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि अनटाड–2 से यह फायदा हुआ है कि लेटिन-अमरीकी कन्ट्रीज चिली और ब्राजील से हम ने मुआहदे किये हैं । हमारी कोशिश यही रही है कि नई नई मार्केटस अपने देश के लिए तलाश करें . .

एक माननीय सदस्य : क्या फिनिश्ड चीज भेजेंगे ।

श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी : फिनिश्ड और सेमी-फिनिश्ड दोनों ।

जहां तक सुपाकर साहब के सवाल का ताल्लुक है—मेरे यहां पर बयान देने के बाद उनकी तसल्ली हो गई होगी कि बहुत सारे देशों के साथ हमारे तिजारती ताल्लुकात बढ़ रहे हैं ।

कोठारी साहब ने कहा ——

We are not exporting ideas or importing ideologies. We are exporting goods and importing goods. So, where does the question of communism or socialism or democracy etc. come in here? It is a question of trade, and when the parties get the best terms of trade they enter into trade agreements; and they do so irrespective of whether it is a communist or socialist or democratic country and so on. Where the parties get the best terms of trade, they enter into agreements. Where we get the best terms of trade, whatever be the type of the country, we shall certainly enter into such trade agreements. So there is no question any ideology coming in here.

अगर कोठारी साहब को यह खतरा है कि उन चीजों के साथ कम्युनिज्म के कुछ जर्म्स यहां पर आ जायेंगे, तो हम उनको डिसइन्फेक्ट कर देंगे, कोई फ़िक्र की बात नहीं है । (व्यवधान)

श्री जार्ज फारनेण्डीज (बम्बई-दक्षिण) : मेरा पहला क्वैश्चन यह था कि प्रधान मंत्री ने पिछले अक्तूबर, में ईस्ट यूरोपियन कन्ट्रीज का दौरा किया था तो उसके सम्बन्ध में भी मंत्री जी बतायें ।

श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी : जहां तक रंधीर सिंह जी का ताल्लुक है, जो बातें मैंने

[श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी]

कही हैं, मेरा खयाल है उनसे वे मुतमईन हो गये होंगे । .. (व्यवधान) .... यादव जी ने एक बात कही कि जो माल हम मगरबी मुल्कों को भेजते हैं, क्या अब ईस्ट यूरोपियन कन्ट्रीज के साथ तिजारत करने से उसमें कोई कमी हुई है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है ।

जहां तक प्रधान मंत्री के दौरे का ताल्लुक है, मैं माननीय सदस्य से अर्ज कर देना चाहता हूं कि फौरन ही हम फालो-अप ऐक्शन लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने पोलैंड, रूमानिया, बलगारिया का दौरा किया तो उसके बाद ही हमने टैक्सटाइल मशीनरी का एक नया सौदा पोलैंड वालों के साथ तकरीबन 5 लाख रुपये का किया और एक दूसरा नया सौदा 30 लाख रुपये का उनके साथ हो रहा है। रूमानिया के साथ कुल मुआहिदे पर दस्तखत होंगे । बलगारिया के साथ हमने टिपर्स का सौदा किया है और उसके बदले में हमने उनसे सिप्रोलिक्टम यूरिया वहां से ली है। इसी तरह से वैगन्स का सौदा जो यू० एस० एस० आर० के साथ है, उसको मैंने पहले ही बतला दिया है। तो एक खास मशीनरी होती है, जिसके जरिये जब कोई वजीर बाहर दौरा करते हैं या प्रधान मंत्री बाहर दौरा करती हैं, उसके बाद फ़ालो-अप ऐक्शन बड़े विगरस तरीके से होता है ।

आखिर में मैं माननीय सदस्यों के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि हम यह बड़े फ़ख्र के साथ कह सकते हैं कि मशरकी मुमालिक के साथ हमारे तिजारती ताल्लुकात काफ़ी तसल्लीबख्श, इत्मीनानबख्श और फायदाबख्श हैं ।

19.7 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the Clock on Thursday, April 4, 1968/Chaitra 15, 1890 (Saka).

GMGIPND—LS II—130 (Ai) LSD—25-9-68—1010.